(d) if so, the steps taken/proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Based on the information available, no State has introduced one family one job scheme.

(b) to (d) Do not arise.

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भू-भाग हेतु केन्द्रीय सहायता

1794. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भू-भाग (उत्तरांचल) के विकास के लिए साधे राशि प्रदान करती है;

(ख) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के दौरान कौन-कौन सी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन राशियों के व्यय पर निगरानी रखने की व्यवस्था भी की है, और

(घ) यदि हां, तो निगरानी की उक्त प्रणाली का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच०ए०डी०पी०) के तहत राज्य के नामित पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वि०के०स० आवंटन*
1995-96	225
1996-97	225
1997-98	225

*"अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम" से विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 7.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इस वित्तीय सहायता का आगे क्षेत्रकीय और स्थानिक वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्कीमें आधारसंरचना विकास, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जल आपूर्ति आदि से संबंधित है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उप-योजना को अंतिम रूप देते समय, वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की जाती है। विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) राज्य सरकार से वास्तविक और वित्तीय रूप से संतोषप्रद प्रगति रिपोर्टों के प्राप्त होने के आधार पर ही जारी की जाती है।

Development of infrastructure in Assam

1795. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of projects pertaining to development of infrastructure including externally aided projects in Assam pending with Government for clearance and since when;

(b) the project-wise reasons for not according approval to these projects and the time by which these are likely to be cleared; and

(c) the total outlay made for development of infrastructure during Ninth Plan (NEC projects to be shown separately)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) The information is being collected and the same will be laid on the table of the House.

(c) The indicative outlay as per the draft of Ninth Five Year Plan for Assam for the development of infrastructure in areas like Irrigation and Flood Control, Power, Transport and Water Supply and Sanitation amounts to Rs. 2995.31 crore. As regards the NEC, schemes/projects are normally taken up for inter-State benefits in the region; however, it is estimated that the share of Assam in the indicative Ninth Plan outlay for the NEC